स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com Website: www.swayamsevi.com

क्रमांक : स्.से.शि.सं.सं.रा./ /2016 दिनांक : 29.02.2016

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारियों के नाम परिपत्र

महोदय,

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन के विरुद्ध विद्यार्थियों का प्रधानमंत्री के नाम एवं संघ का विधायको के नाम परिपत्र संलग्न है। विद्यार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपने स्कूल के लेटर पैड पर लें ले और उनकी प्रतिलिपि संघ कार्यालय में email: swayamsevirajasthan@gmail.com पर भेंजे तथा अपने क्षेत्र के अखबारों को भी समाचार दें। तथा अपने अपने क्षेत्र में रैलियां और धरने प्रदर्शन आयोजित करें।

भवदीय !

(सत्यव्रत सामवदा)	(श्रीराम डंगायच)	(किशन मित्तल)
अध्यक्ष	महामंत्री	मंत्री
9829052697	9414040533	9829523349

नोट – विद्यार्थियों का ज्ञापन बनाकर शीघ्र वेबसाईट पर डाला दिया जायेगा।

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com Website: www.swayamsevi.com

क्रमांक : स्.से.शि.सं.सं.रा./ /2016 परिपत्र – 1 दिनांक : 29.02.2016

निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के समाधान हेतु विधायकों को ज्ञापन

महोदय,

आप इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी भी प्रांत की पहली प्राथमिकता शिक्षा है और केन्द्रीय बजट प्रस्तुत होने से पूर्व समस्त राजनैतिक, सामाजिक नेताओं और शिक्षा शास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि बजट में सर्वाधिक योगदान शिक्षा का होना चाहिए। आप इस तथ्य से भी अवगत है कि राजस्थान की नई पीढ़ी के भविष्य का निर्माण शिक्षण संस्थाएं करती आ रही हैं और राजस्थान के विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का श्रेय निजी शिक्षण संस्थाओं को जाता है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 90 प्रतिशत संस्थाओं में उन परिवारों के बच्चे होते है जिनकी आय 5000 रुपये से भी कम है और उनसे जब फीस प्राप्त होती है, उससे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, वह नरेगा के मजदूरों से भी कम होता है। इतने कम वेतन में उत्कृष्ठ शिक्षा देने वाले शिक्षकों के प्रति यह अत्याचार ही है। इसके बावजूद निजी शिक्षण संस्थाओं के अस्तित्त्व को समाप्त करने लिए 1993 से प्रयास चल रहे हैं और निजी शिक्षण संस्थाओं की ऊर्जा का गत 22–23 वर्षों से इसी संघर्ष में अपव्यय हो रहा है। संविधान के अनुसार निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य है परंतु इस कर्त्तव्य का निष्पादन सरकार से एक पैसे की भी आर्थिक सहायता लिए बिना निजी शिक्षण संस्थाऐं कर रही हैं।

अतः आपसे से अपेक्षा है कि आप निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा में आवाज उठाएं और सरकार को निजी शिक्षण संस्थाओं के हित में कार्य करने के लिए नीति निर्धारण करने के लिए भी परामर्श दें। –

1. **महाराष्ट्र विधेयक को राजस्थान में लागू करने का विरोध करें** क्योकि विद्यालय फीस का निर्धारण एक कमेटी करेगी जिसमें विद्यालय के 5 अभिभावक, 3 अध्यापक, 1 प्राचार्य, 1 प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष होगा। फीस निर्धारण प्रबन्ध समिति, संस्थाओं के व्यय के अनुसार करती है इस विधेयक से प्रबन्ध समिति की स्वायत्ता छीनी जा रही है जो शिक्षा के दृष्टि से बहुत घातक होगी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधेयक पर निषेधाज्ञा जारी की हुई है।
2. **शिक्षा का बजट दुगुना किया जाये–** दिल्ली में आप सरकार ने शिक्षा के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए बजट को दुगुना कर दिया है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। उत्कृष्ठ शिक्षा देने वाले निजी शिक्षण संस्थओं के अध्यापकों को बहुत कम वेतन में काम करना पड़ रहा है अतः जितना वेतन निजी शिक्षण संस्थाएं दे पा रही हैं उतना ही वेतन सरकार निजी शिक्षण संस्था के कर्मचारियों को सहयोग रुप में दें।
3. **पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन का विरोध किया जाये** क्यौंकि शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने एनसीईआरटी की पुस्तकों को हटा कर संकीर्ण मनोवृत्ति से घटिया पुस्तकें निर्धारित की है जिसमें से कवि सूरदास, कबीरदास जैसे सहित्याकारों को हटा कर टेऊमल और हेमूकालानी की जीवनी डाल दी गई है। एनसीईआरटी की पुस्तकों के कारण राजस्थान के विद्यार्थी किसी भी प्रांत में प्रवेश ले सकते थे और प्रतियोगी परीक्षाओं में कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। नई पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने पर लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिसे रोकना आपका दायित्त्व है।
4. **ई.एस.आई. समाप्त की जाये**। राजस्थान की अधिकांश संस्थाएं घटे में चल रही हैं और ईएसआई के प्रावधान के कारण घोर आर्थिक संकट से गुजर रही हैं और इससे कर्मचारियों का भी कोई हित नहीं हो रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर राजस्थान के हित में सहयोग दें।

भवदीय!

सत्यव्रत सामवेदी	श्रीराम डंगायच,	रतन सिंह पिलानियां,	एल.सी. भारतीय	किशन मित्तल,
प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	प्रदेश महामंत्री	जयपुर अध्यक्ष	प्रदेश मंत्री
9829052697				9829523349

उपाध्यक्ष – आचार्य लोकेन्द्र शर्मा, सज्जन सिंह पूनियां, कृष्ण कुमार शर्मा, बाबूलाल जूनेजा

जिला अध्यक्ष – अनंतराम आर्य–भरतपुर, जगन सिंह चाहर–सीकर, सुरेन्द्र सिंह अहलावत–झुंझुनू, एम.पी. खुराना–अलवर, राजवीर सिंह–चुरु, कोडाराम भादू–बीकानेर, सुशील जेटली–गंगानगर, हितेश श्रीमाली–उदयपुर, महेन्द्र कर्नावट–राजसमंद, बन्नाराम पंवार–जोधपुर, अनुज

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com Website: www.swayamsevi.com

क्रमांक : स्.से.शि.सं.सं.रा./ /2016 परिपत्र – 2 दिनांक : 29.02.2016

राजस्थान के राजनैतिक दलों के अध्यक्षों , सांसदों एवं विधायकों के नाम परिपत्र

विषय :– राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यपुस्तकों के परिवर्तन के सम्बन्ध में

महोदय,

हम आपका ध्यान राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यपुस्तकों के परिवर्तन से उत्पन्न विद्यार्थियों के अहित की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध 80 हजार सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में एनसीईआरटी की पुस्तकें सत्र 2015–16 तक पाठ्यक्रम में थी। इस प्रकार देश में समान पाठ्यपुस्तकें होने के कारण राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी भारत वर्ष के किसी भी प्रांत में प्रवेश ले सकते थे। इसके अतिरिक्त इन पाठ्यपुस्तकों के स्तर के कारण विद्यार्थी प्रतिस्पृद्धि परीक्षाओं में भाग लेकर उत्तीर्ण हो रहे थे और उनका भविष्य निर्माण हो रहा था तथा सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों का विद्यार्थियों को विकल्प मिल गया था जिस कारण राजस्थान बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में विद्यार्थी भारी संख्या में प्रवेश लेने लगे थे।

परन्तु आगामी सत्र के लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने निहित, संकीर्ण एवं क्षेत्रीय विचाराधार से प्रेरित होकर पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन कर 300 करोड़ रुपये की पुस्तकें छपवाने का कार्य शुरु कर दिया है जबकि एनसीईआरटी की 50 करोड़ की पुस्तकें पाठ्यपुस्तक मंडल में रखी हुई है। इस प्रकार गरीब जनता के 300 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार द्वारा राजकोष से बर्बाद किये जा रहें है। नये सत्र में जो पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं उनका स्तर अत्यन्त सोचनीय है इन पुस्तकों में से विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई, कवि सूरदास, कबीरदास जॉन कीट्स, पी. एस. ईलयट जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को हटा कर टेऊमल और हेमूकालानी जैसे अज्ञात लोगों को महिमामंडित किया गया है। सरकार की शिक्षा विभाग की इस नीति से विद्यार्थियों और अभिभावकों में भंयकर आक्रोश है और राजस्थान के बुद्धि जीवियों ने इस परिवर्तन की कटु आलोचना की है। हिन्दुस्तान टाईम्स और टाईम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार संलग्न है। शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा लाखों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना निंदनीय कार्य है।

हम आपको इस तथ्य से भी अवगत कराना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने 66 सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए सीबीएसई से मान्यता लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। जब राजस्थान सरकार ही सीबीएसई के पाठ्यक्रम को मॉडल मान रही है तो अन्य विद्यालयों को नये पाठ्यक्रम के लिए बाध्य क्यों कर रही है ?

अतः आपसे आग्रह है कि करोड़ों विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की भावनाओं को दृष्टि गत रखते हुए पाठ्यपुस्तकें के परिवर्तन का विरोध करें और विधान सभा के सत्र में करोड़ों विद्यार्थियों के हित में पाठ्यपुस्तकों के परिवर्तन को रोकें।

भवदीय !

(सत्यव्रत सामवेदी)
अध्यक्ष
9829052697

(किशन मित्तल)
मंत्री
9829523349

जिले के पदाधिकारी–

New Raj textbooks drop major western writers

Lesser-Known Authors With Regional Flavour Included

Shoeb.Khan@timesgroup.com

Jaipur: The BJP government in Rajasthan has omitted poems by the likes of John Keats, Thomas Hardy, William Blake, T S Eliot and Edward Lear from the revised Class VIII English textbooks. They have been replaced by mostly lesser-known authors whose works have a regional flavour.

So while Hardy's 'When I Set Out For Lyonnesse', Eliot's 'Macavity: The Mystery Cat' and Blake's 'The School Boy' have been dropped, works such as 'My first visit to the bank', 'The Brave Lady of Rajasthan', 'Chittor', 'Sangita the brave girl' have been included in the first lot of revised textbooks that have arrived at state textbook depots in Ajmer, Udaipur, Dausa, Bharatpur and Jaipur. Last year, Rajasthan had re-written textbooks from Class I to XII in a period of less than three months.

The books that have arrived include those for Class VIII (Hindi, English, Sanskrit, maths) and Class VI (English, Hindi, maths). They have been confined in the godowns of state textbooks depots. Foreign authors were dropped as part of the education department's directive to the textbook rewriting committee to include content that evokes a sense of pride in the state and the country. Swami Vivekananda's 'The song of the free' and Rabindranath Tagore's 'Where the mind is without fear' are among the additions.

The Class VIII Hindi textbook has also undergone a complete overhaul. Urdu author Ismat Chugtai's short story 'Kamchor' and Hari Shankar Parsai's 'Bus Ki Yatra' have been omitted. Veteran journalist P Sainath's '*Jaha Pahiya hai*' ('Where there is a wheel'), which talks about bicycles becoming a symbol of women emancipation, was also dropped by the textbook rewriting committee.

"Most of the Hindi chapters that were dropped were loaded with Urdu words, which were difficult for the students to understand," said a member of the textbook committee on the condition of anonymity. "We were also directed to strike out those chapters whose theme revolves around a particular faith."

Satyavrat Samvedi, president of Swayamsevi Shikshan Sanstha, a body of private schools affiliated to the Rajasthan Board of Secondary Board, said: "If all new books are based on the same premise of promoting local region, then we are on a different path from other states. This will result in poor performance of our students in national-level competitions."

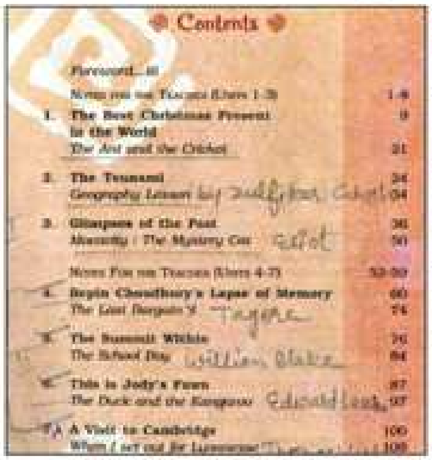

Lesson No.	Lesson Name
1.	Chittor
2.	Animals' Strike
3.	The Praying Hands
4.	The Felling of the Banyan Tree
5.	Life in K.G.B.V.
6.	The Brave Lady of Rajasthan
7.	The Song of The Free
8.	Chanakya the Great
9.	Sangita the Brave Girl
10.	The Glory of Rajasthan

Content list of old and new Class VIII English textbook

The Hindustan Times
ESTABLISHED IN 1924

Make the grade in today's world

Restricting western influences denies students the means to hold their own on a global stage

ourtake

The effort to recast the curricula in schools and inculcate a sense of desi values in students at all levels seems to have become an obsession with both the Hindutva forces and some BJP-led state governments. The latest is the Rajasthan government, which has decided to drop poems by John Keats, Thomas Hardy, William Blake, TS Eliot and Edward Lear, among others from school books. Additions to the curriculum include works like 'My visit to the bank' and 'Sangita the brave girl'. In another move, Banaras Hindu University has decided to undertake a year-long effort to educate students of the ills of western culture.

Rewriting textbooks in Haryana was in the news, thanks to the initiative of Dinanath Batra, the man who shot to fame for his contribution to publishers pulping Wendy Doniger's seminal work on Hinduism. It is no one's case that students should not learn about Indian culture or not study the works of Indian authors. But to restrict access to western literature is to deny them vistas of learning which will equip them to hold their own in a globalised world. Whether we like it or not, the knowledge of English is a great advantage when competing on the global stage and we are rightly proud of this. We should not fritter away this advantage due to some misplaced sense of nationalism. Why should students be denied knowledge or the sheer reading pleasure from the great works of English literature?

Often, these decisions to chop and change the curriculum are motivated by political considerations. Many of our netas who advocate Indianisation of the curriculum or lecture people on the evils of western culture make sure that their own children get an English-medium schooling and higher education abroad. In Rajasthan both the Indian works and the English ones can be learnt by students, it should not be a case of one or the other. The main aim of education should be to enable and empower students as they progress through the system and into the job market. Today, the market is not limited by borders. In the past, state governments like that in West Bengal abolished English as a medium of instruction. This led to an entire generation for whom employment opportunities were restricted. Current dispensations should at least take a leaf or two out of past books where efforts to stamp out foreign influences have not paid off.

मॉडल स्कूलों में लगेगी विज्ञान संकाय की कक्षाएं

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होगी संबद्धता

बीकानेर @ पत्रिका. राज्य के 21 जिलों में चल रही 66 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अगले सत्र से कक्षा 11 में सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप शिक्षण होगा। इसके लिए इन स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड से कक्षा बारहवीं की मान्यता ली जाएगी। इन स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। सत्र 2016-17 में इन 66 मॉडल स्कूलों में विज्ञान वर्ग में गणित व जीव विज्ञान विषय शुरू किए जाएंगे।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त आयुक्त जस्साराम ने जिन 21 जिलों में ये विद्यालय संचालित हो रहे है उन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को इन स्कूलों की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।

पांच विषय पढ़ने होंगे

इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कुल पांच विषय पढ़ने होंगे । एनसीईआरटी के अंग्रेजी इलेक्टीव, फिजिक्स, केमेस्ट्री तो पढ़ने ही होंगे तथा चौथे विषय के रूप में बॉयोलॉजी व गणित विषय में से किसी एक विषय को चुनना होगा।

12 जिलों में नहीं स्कूल

बारह जिलों में एक भी मॉडल स्कूल नहीं है। इनमें बीकानेर, हनुमानगढ़ ,जयपुर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, झुंझनू, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली शामिल है।

जर्जर स्कूल भवनों की रिपोर्ट मांगी

राजस्थान पत्रिका

खबर का असर

बीकानेर @ पत्रिका. शिक्षा विभाग अब सभी सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की स्थिति का आकलन करने में जुट गया है। राजस्थान पत्रिका के बुधवार के अंक में प्रकाशित खबर 'आठ साल से अच्छे दिन के इंतजार में है बच्चे' पर हरकत में आए विभाग ने संस्था प्रधानों से स्कूल भवनों व कमरों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है।